14.07.2020

बी०ए० - खण्ड - 1
अर्थशास्त्र (ऑ०) - द्वितीय पत्र
"मुद्रा-स्फीति" (Inflation Effect & Control)

डॉ० विपिन कुमार
प्रो० (अर्थशास्त्र विभाग)
आर०आर०एस० कॉलेज मोकामा
पी०पी०यू०, पटना

प्रश्न: What is Inflation? Explain its effects and control.

उत्तर: सामान्यतः मुद्रा-स्फीति से तात्पर्य होता है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत-स्तर में लगातार वृद्धि हो और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो ऐसी स्थिति को "मुद्रा-स्फीति (Inflation)" कहा जाता है।

वहीं दूसरी ओर अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में कीमत कुछ समय के लिए बढ़ती है और फिर कम हो जाती है और फिर दुबारा बढ़ती है तो हम इसे मुद्रा-स्फीति नहीं कहेंगे। मुद्रा स्फीति में सामान्य कीमत-स्तर लगातार बढ़ना चाहिए। जहाँ एक निश्चित आय वर्ग के लोगों पर मुद्रा-स्फीति का बुरा असर पड़ता है कारण कि उनकी आय कम होती है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनकी क्रय क्षमता कम हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति का बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो मुद्रा स्फीति की कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है लेकिन विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा निम्नांकित रूप में दिया है:

(i) बहुत ही कम माल के लिए बहुत अधिक की पूर्ति हो जाने से यह उत्पन्न होती है।
(ii) माल या सेवा की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाने पर भी इसका जन्म होता है।
(iii) आपूर्ति में दोष, गत्यावरोध या दोषपूर्ण असंतुलन के चलते भी मुद्रा स्फीति की उत्पत्ति देखी गयी है।

अब हम मुद्रा स्फीति का किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक या अनार्थिक क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे:

(1) निश्चित आय वर्ग के लोगों पर प्रभाव: इसके तहत वैसे लोग जिनकी आय प्रायः निश्चित होती है यथा, शिक्षक, श्रमिक, एवं सहित अन्य नौकरी पेशा वाले व्यक्ति, क्योंकि मुद्रा स्फीति के कारण जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर निश्चित आय वाले लोगों पर पड़ता है और उन्हें इससे नुकसान होता है।

(2) निवेशक पर प्रभाव: इसके तहत दो प्रकार के निवेशक होते हैं - पहला वर्ग निवेशक वर्ग होता है जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जिससे उन्हें निश्चित आय की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरे निवेशक वैसे लोग हैं जो संयुक्त पूंजी कम्पनियों के हिस्से की खरीददारी करते हैं। इनकी आय मुद्रा स्फीति होने पर बढ़ती है अर्थात इस दूसरे वर्ग को Inflation लाभ और पहले वर्ग को हानि उठाना पड़ता है।

(3) बचत पर प्रभाव: बचत पर मुद्रा-स्फीति का विपरीत असर होता है। मुद्रा-स्फीति के कारण वस्तुओं पर किये गए व्यय में वृद्धि होती है, इससे बचत की क्षमता घट जाती है। दूसरी ओर मुद्रा स्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग इससे बचत करना नहीं चाहेंगे।

(4) ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव : इसके तहत ऋणी को लाभ जबकि ऋणदाता को नुकसान होता है क्योंकि जब ऋणदाता अपना रुपया किसी को उधार या कर्ज के रूप में देता है तो मुद्रास्फीति के फलस्वरूप रुपये का मूल्य घट जाता है। इससे ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि तथा ऋणी को लाभ पहुँचता है।

(5) सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव : इसके तहत मुद्रा-स्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है क्योंकि जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो सरकार को सार्वजनिक योजनाओं पर अपना व्यय भी बढ़ाना पड़ता है -- इस व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार को जनता से कर्ज (ऋण) लेना पड़ता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है या उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

(6) करों पर प्रभाव : मुद्रास्फीति के फलस्वरूप सरकार के सार्वजनिक व्यय में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। इससे सरकार को जनता पर कई प्रकार के नये कर लगाने पड़ते हैं इसके साथ ही पुराने करों की दरों में वृद्धि करनी पड़ती है -- इस तरह से मुद्रास्फीति करों के भार में वृद्धि करती है।

(7) भुगतान संतुलन पर प्रभाव : मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। इसके कारण हमारे निर्यात महँगे हो जाएँगे जबकि आयात सस्ते हो जाएँगे। इससे निर्यात महँगा तथा आयात सस्ता हो जाता है -- इसका सीधा प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है अर्थात् भुगतान संतुलन असंतुलित (प्रतिकूल) हो जाता है।

(8) उत्पादकों पर प्रभाव : उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को मुद्रा-स्फीति के कारण मुनाफा (लाभ) होता है। कारण कि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति उद्यमी तथा उत्पादकों को काफी फायदा होता है।

(9) किसानों पर प्रभाव : किसानों पर मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है कारण कि कृषक वर्ग उत्पादन करता है तथा मुद्रा-स्फीति के दौरान उत्पादन की कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार, मुद्रास्फीति के दौरान किसानों को लाभ होता है।

(10) नैतिक प्रभाव : मुद्रास्फीति के कारण व्यापारी वर्ग लोभ-लालच में अंधा हो जाता है और मुनाफाखोरी, मिलावट तथा जमाखोरी आदि का प्रयोग उत्पादन को बेचने में करते हैं। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तथा इससे लोगों में नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है।

उपरोक्त प्रभावों के बाद अब हम मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपायों

Appointments

की जा सकती है।

(1) मौद्रिक उपाय: मौद्रिक नीति के तहत मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कई मौद्रिक उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है:

(i) मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण: मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर के मुद्रा स्फीति पर काबू पाया जा सकता है और मुद्रा की मात्रा को केन्द्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह, जब केन्द्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा पर कड़ा नियंत्रण लागू करे तो मुद्रा की मात्रा नियंत्रित हो जायेगी।

(ii) विमुद्रीकरण: जब मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण संभव नहीं हो तो सरकार विमुद्रीकरण का सहारा लेती है। विमुद्रीकरण के तहत सरकार पुरानी करेंसी की जगह, नयी करेंसी लेकर आती है- जिससे मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में लाना संभव हो पाता है।

(iii) साख नियंत्रण: मुद्रा स्फीति के दौरान केन्द्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर सकती है। साख नियंत्रण हेतु सरकार परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही उपायों को प्रयोग में लाती है। इस उपाय के अंतर्गत बैंक दर में वृद्धि, रेपो दर तथा न्यूनतम नकद कोष में वृद्धि, प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना, साख की राशनिंग तथा सीमान्त आवश्यकता में वृद्धि कर सकता है।

(2) राजकोषीय उपाय: इसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय अपनाये जाते हैं:

(i) सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि: मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में स्वतः वृद्धि हो जाती है। ~~क्योंकि मुद्रास्फीति के फलस्वरूप मांग में वृद्धि आती और मांग में~~ वृद्धि मांग को पूरा करने के लिए सरकार निजी व्यक्तियों से कर्ज ले सकती है। जब किसी क्षेत्र से ऋण लिया जायेगा तो निजी क्षेत्र के व्यय में कमी हो जायेगी। इस प्रकार, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके भी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।

(ii) करों में वृद्धि: मुद्रा स्फीति के कारण सार्वजनिक व्यय में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु सरकार लोगों पर कई प्रकार के कर लगाती है तथा ही पुराने करों में वृद्धि भी कर देती है। इन कर की दरों में वृद्धि का भी मांग पर (प्रतिकूल प्रभाव) उत्पादन पर पड़ता है।

(iii) सार्वजनिक व्यय में कमी: मुद्रा स्फीति के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसमें वृद्धि से लोगों की मांग में भी वृद्धि होने लगती है तथा मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि होगी। इस तरह, सार्वजनिक व्यय में कमी करके भी हम मुद्रा स्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं।

(iv) घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी : यह उपाय तब अपनाया जाता है जब सरकार की आय उसके द्वारा किये गए व्यय से कम रह जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार नई मुद्रा को जारी करती है और अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा नई मुद्रा को जारी की जाती है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। अतः मुद्रास्फीति को कम करने के लिए या नियंत्रित करने हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था को अधिकतम हद तक कम करना होगा।

(3) अन्य उपाय : मुद्रा पर नियंत्रण पाने के लिए मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख उपाय भी हैं जो निम्नलिखित हैं :

(i) उत्पादन में वृद्धि के द्वारा : इस विधि को अपना कर भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। कारण कि मुद्रास्फीति की स्थिति तभी पैदा होती है जब कुल माँग कुल पूर्ति से अधिक हो जाता है। इस प्रकार हम कुल पूर्ति या उत्पादन को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को काबू में कर सकते हैं।

(ii) कीमत नियंत्रण तथा राशन व्यवस्था : इन उपायों से भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाना संभव है। राशनिंग व्यवस्था के तहत कीमत स्तर भी अधिक नहीं बढ़ता है तथा सभी लोगों को अपनी जरूरत के मुताबिक सामान (वस्तुएँ) भी प्राप्त हो जाती हैं।

(iii) बचत को प्रोत्साहित कर : मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का यह भी एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। इसके तहत सरकार को बचत को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए। जब बचत में वृद्धि होती है तब निजी व्ययों में कमी होती तथा माँग स्वयं ही कम हो जाएगी तथा कीमत स्तर भी काबू में आ जाएगा।

उपरोक्त विश्लेषण से मुद्रास्फीति, इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव एवं इसके नियंत्रण के ~~उपायों~~ उपाय स्पष्ट हो जाते हैं।

N.B. : आगामी कक्षा में 'Inflationary Gap' की चर्चा की जाएगी।